भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1719
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

द्वीप का आर्थिक विकास

†1719. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा द्वीप संघ राज्यक्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): महोदय, सरकार ने पर्यटन, डिजिटल/दूरसंचार कनेक्टिविटी, सड़क/हवाई/समुद्री कनेक्टिविटी, अवसंरचनात्मक विकास, शासन सुधार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन को इसके बहुगुणक प्रभाव के कारण एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और द्वीपों में पर्यावरण-पर्यटन, क्रूज पर्यटन, सांस्कृतिक, विरासत, साहसिक पर्यटन और पर्यटक सर्किट जैसी विभिन्न पर्यटन गतिविधियों/पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने पक्षी अवलोकन, कारवां पर्यटन, लक्जरी टेंट, खगोल पर्यटन और हाउसबोट पर्यटन के लिए नवोन्मेषी नीतियां बनाई हैं। इसके अलावा, होटल आवास की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शहीद द्वीप, एवेस और लॉन्ग द्वीप में पर्यावरण-पर्यटन परियोजनाएं और श्री विजयपुरम में मेगापोड रिसॉर्ट की ब्राउनफील्ड परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, स्वराज द्वीप पर राधानगर बीच (Beach) को ब्लू फ्लैग बीच (Blue Flag Beach) के रूप में प्रमाणित किया गया है और 10 अन्य समुद्र तटों को भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चिन्हित किया गया है।

इसी प्रकार, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप ने कदमत और सुहेली द्वीपों पर पीपीपी मॉडल के तहत अपनी तरह के पहले लैगून विला विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। बंगारम द्वीप पर पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही आवास की मांग को पूरा करने के लिए, 50 लग्जरी टेंटेड स्टे (Tented Stay)अब चालू कर दिए गए हैं। मिनिकॉय स्थित थुंडी बीच (Beach) और कदमत बीच (Beach) को ब्लू फ्लैग बीच (Blue Flag Beach) का दर्जा मिल चुका है और दो और बीचों (Beaches) को भी इसी तरह के प्रमाणीकरण के लिए चिन्हित किया गया है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाने और नागरिकों को इसके फायदे पहुंचाने के लिए, चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के चालू होने से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) में डिजिटल/दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतनेट के अंतर्गत, सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायतें और जनजातीय परिषदें जुड़ चुकी हैं। इसी तरह, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह (KLI) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (KLI-SOFC परियोजना) ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के सभी आबाद द्वीपों को सबमरीन केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। दोनों द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के लिए सैटेलाइट ट्रांसपोंडर के माध्यम से अतिरिक्त कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की गई है।

द्वीपों के लिए हवाई संपर्क के महत्व को देखते हुए, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने श्री विजयपुरम में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित आधुनिक टर्मिनल भवन को चालू कर दिया है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 50 लाख यात्रियों को संभालने की है। द्वीपों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए श्री विजयपुरम से कार निकोबार, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, कमोर्ता, कचल, चौरा, टेरेसा, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और कैंपबेल बे के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, संघ राज्यक्षेत्र ने डिगलीपुर, कार निकोबार और कैंपबेल बे को 19 सीटों वाले Fixed विमान से जोड़ने की योजना बनाई है। इसी तर्ज पर, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप ने मुख्य भूमि (कोच्चि, गोवा और बेंगलुरु) से अगाती द्वीप के लिए नियमित उड़ानों की सुविधा सुनिश्चित की है। द्वीपों के बीच संपर्क के लिए, द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में फेरी सेवाएं उपलब्ध हैं, वहीं इन संघ राज्यक्षेत्रों के कई द्वीपों पर सीप्लेन सेवाएं भी शुरू करने की योजना है।

चूंकि अवसंरचना आर्थिक विकास की नींव रखती है, इसलिए द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में सड़कें, पत्तन, घाट, जहाजरानी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल शासन आदि जैसी कई अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना एवं रसद विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, जलीय कृषि, समुद्री शैवाल की खेती, क्षमता निर्माण आदि कार्य किए जा रहे हैं।

दोनों द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में, सरकार ने समावेशी विकास, आजीविका सृजन, अवसंरचना निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सशक्त निगरानी तंत्र के साथ प्रमुख योजनाओं का प्रभावी और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। इन योजनाओं का उपयोग कनेक्टिविटी, पेयजल और स्वच्छता कवरेज, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आवास, मत्स्य पालन और लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की आजीविका, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इस समन्वय-आधारित दृष्टिकोण ने अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार किया है, रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है और सामाजिक कल्याण परिणामों को बढ़ाया है, विशेष रूप से दूरस्थ द्वीपीय बस्तियों में।

उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, कारोबार की सुगमता और उदारीकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ अनुपालन का बोझ काफी कम कर दिया गया है, जिससे निवेश का भरोसा बढ़ा है और आर्थिक गतिविधियां व्यापक हुई हैं। पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करके निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई हैं।

सरकार की इन पहलों से द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास हुआ है। भारत सरकार का प्रयास है कि द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों को सुशासन और विकास का प्रेरणा-स्रोत (role model) बनाया जाए।